nwda.gov.in

हाथ जुड़े, अब नदियां जुड़ेंगी • केंद्रीय जलशक्ति मंत्री, मप्र और राजस्थान के सीएम ने त्रिपक्षीय समझौते पर किए हस्ताक्षर

मप्र-राजस्थान के बीच 75 हजार करोड़ की नई नदी जोड़ो परियोजना, जुड़ेंगी चंबल-पार्वती-कालीसिंध व 6 नदियां

मप्र में बनेंगे 17 डैम और बैराज, 12 लाख हेक्टेयर जमीन होगी सिंचित

90% राशि केंद्र देगा, दोनों राज्यों को अपने हिस्से का 10% ही देना होगा

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मप्र और राजस्थान ने चंबल और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे का विवाद सुलझाने के लिए केंद्र की मध्यस्थता में एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इसके तहत राजस्थान की ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) और मप्र की संशोधित पार्वती-कालीसिंध और चंबल (पीकेसी) लिंक परियोजना को आपस में जोड़कर एक नई राष्ट्रीय नदी परियोजना तैयार की जाएगी। चंबल की सहायक नदियों पार्वती, कालीसिंध, क्षिप्रा, कूनो, लखुंदर, मेज, क्यूल, बनास नदियों पर कुल 22 बांध और बैराज बनेंगे। इनमें 17 बांध और बैराज मप्र में और 5 राजस्थान में आकार लेंगे। इस पूरी परियोजना पर लगभग 75 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसकी 90 फीसदी राशि केंद्र सरकार देगी। दोनों राज्यों को अपने-अपने हिस्से के प्रोजेक्ट की सिर्फ 10 फीसदी लागत वहन करनी होगी।

दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। शेष | पेज 13 पर

2004 में बना था खाका, 20 साल बाद बनी यह सहमति

5 साल में आकार लेगी परियोजना : मोहन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह परियोजना 5 वर्ष में आकार लेगी, जिससे मप्र और राजस्थान की 1.5 करोड़ आबादी सीधे लाभान्वित होगी। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि दोनों राज्यों के 26 जिले की 5.60 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।

मध्यप्रदेश के लिए बड़ी सौगात : सिलावट

मप्र के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मप्र के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इससे मप्र में 4 लाख 12 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित बनाया जा सकेगा। इस परियोजना का खाका 2004 में तैयार हुआ था, लेकिन दोनों राज्यों में 20 साल बाद सहमति बन सकी है।

मप्र में सबसे ज्यादा फायदा उज्जैन को...

सिंचाई हो या पेयजल या फिर बांध...इस परियोजना से अगर किसी जिले को सबसे अधिक फायदा होता दिख रहा है तो वह उज्जैन ही है।

सिंचाई में उज्जैन की सबसे अधिक जमीन को फायदा

▪ उज्जैन	65 हजार हेक्टेयर
▪ शाजापुर	46 हजार हेक्टेयर
▪ धार	10 हजार हेक्टेयर
▪ इंदौर	12 हजार हेक्टेयर
▪ आगर-मालवा	4 हजार हेक्टेयर

चंबल संभाग के शिवपुरी, श्योपुर, गुना, ग्वालियर, मुरैना, भिंड में 2 लाख हेक्टेयर

पेयजल में उज्जैन, इंदौर और चंबल को फायदा...

- **मालवा क्षेत्र के**- इंदौर, उज्जैन, धार, आगर-मालवा और शाजापुर जिलों को 150 मिलियन घनमीटर पेयजल उपलब्धता
- **चंबल क्षेत्र के** - शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, मुरैना, भिंड को 20 मिलियन घनमीटर पेयजल उपलब्ध होगा।

चंबल अपर बेसिन में 7 बांध : सबसे बड़ा उज्जैन में

गांधी सागर डैम के अपस्ट्रीम में चंबल नदी पर 5 नए बांध बनेंगे, एक -एक बांध क्षिप्रा और गंभीर नदी पर बनेगा। इनमें सबसे बड़ा उज्जैन के चित्तावर गांव में 200 एमसीएम जल भंडारण क्षमता का नया बांध बनेगा। सोचचिरी, रामबासा, बचोरा, पदुनिया, सेवरखेरी और सीकरी सुल्तानपुर में 6 छोटे बांध।